भारतीय अश्व संस्था द्वारा भारत सरकार को ज्ञापन
निर्यात – भारतीय मूल के अश्व

आवश्यक बिन्दु

भारत में मारवाडी, काठियावाडी, मणीपुरी सहित अन्य भारतीय मूल के अश्वों की बडी जनसंख्या है

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई अश्व गणना यह स्पष्ट करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारतीय मूल के अश्वों की संख्या किसी भी रुप में खतरे की श्रेणी में नही आती।

भारतीय अश्व देश की विरासत एवं सॉस्कृतिक धरोहर है और भारत सरकार की विरासत संरक्षण नियमें की तरह इनकी भी सुरक्षा एवं प्रसार होना चाहिये।

भारतीय अश्वों के प्रति हाल ही में आये सकारात्मक परिवर्तन व चयनित breeding के चलते भारतीय अश्वों ने न सिर्फ पूरे देश में वरन् अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और आज ये विश्व में ''भारतीय राजदूत'' की तरह माने जाते है।

अन्तर्राष्ट्रीय अश्व जगत ने उन अश्व पालकों, किसानों एवं व्यक्तियों के प्रयासों को सराहा है जिन्होनें भारतीय अश्व का अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं खेलो के माध्यम से विश्व के सामने प्रस्तुत कर इसका मान बडाया है।

भारतीय मूल के अश्वों के प्रजनन और इनको अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बढावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिये लभप्रद होगी और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी।

समस्या

अश्व पालकों व संस्थाओं के मतभेद भारतीय अश्व निर्यात के लिये हानिकारक है।

मारवाडी, काठियावाडी, मणीपुरी अश्वों पर किसी भी प्रकार का restriction (रिस्ट्रीक्शन) रखना स्थानीय आय के लिये हानिकारक है और यह विदेशी निवेश को कम करेगी।

भारतीय मूल के अश्वों की वर्तमान निर्यात पौलिसी अव्यवाहरिक, उलझी हुई तथा धीमी प्रक्रिया की है।

मॉग

अश्व निर्यात पौलिसी पर पुनः विचार किया जाये और ऐसी पौलिसी तैयार हो कि सब संम्बधित पक्षों को बराबर का लाभ मिले।

निर्यात पौलिसी बनाते समय अधिक से अधिक संस्थाओं, किसानों व अश्व पालकों के विचार लिये जायें।

सभी भारतीय मूल के अश्वों के लिये एक राष्ट्रीय स्टड बुक (National Stud Book) बनाई जाये।

यूरोप में निर्यात हेतु disease free zone बनाया जाये।

सरकार का जिन देशों के साथ अश्व आयात निर्यात पौलिसी के तहत medical protocol नहीं है उनके साथ इस विषय में तुरन्त कार्यवाही आरम्भ की जाये।